

Shri C. M. Poonacha: Here, it is contract labour which is working. According to the information that I have, the contract labour during the past three or four months has been as follows: it was 159 per day during April, 124 during May and 60 during June. It is varying from month to month according to the traffic that is being handled.

श्री कंबर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह अनइकानोमिक है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कितना अनइकानोमिक है और इस में कितना घाटा होता है और इस बारे में फ़ाइनल डिजिज़न कब हो जायेगा।

Shri C. M. Poonacha: After we had taken a decision to close this, certain matters were brought to our notice, and so, we have deferred the decision. We are going into the question now, and we are considering whether in addition to the facilities that we have at Farakka, we should continue in this sector also. We shall examine this, and I think that in a couple of months we should be able to take a decision.

Shri P. G. Sen: Is the Minister aware that this line feeds the Calcutta line and the area through which this route passes and where the Ghat is situated is a jute producing area? Has he taken into consideration the export of jute from this area, North Bengal and Bihar, to Calcutta via this route?

Shri C. M. Poonacha: Yes, that traffic is also taken into consideration.

पाकिस्तान न द्वारा रोके गये माल का लौटवारा
जान:

+

*1592. श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री बहदानन्दजी :

श्री हुकाम चन्द कछवा

श्री बी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री 26 मई, 1967 के तारोंकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सम्बन्ध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाजों तथा माल को वापस प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ये जहाज और माल कब तक वापस मिल जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कितना समय और लगने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) तथा (ख). पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाजों और जन्त किये गये माल में से अब तक केवल दो जहाज और 70.14 लाख रुपये का माल वापिस आया है।

(ग) संघर्ष के दौरान, दोनों सरकारों द्वारा जन्त किये गये जहाजों, माल, सम्पत्तियों परिसम्पत्तियों आदि को छोड़ने के सम्पूर्ण मामले को तय करने के लिये बार बार किये गये हमारे प्रयत्नों का पाकिस्तान सरकार से कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है, इस लिये इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि इस मामले को तय करने में कितना समय और लगेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : ताशकंद घोषणा के अनुसार जो व्यवस्था हुई थी, उस में रूस एक मध्यस्थ था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने पाकिस्तान की इन हरकतों की तरफ रूस का ध्यान दिलाने की कोशिश की है और रूस ने अपने कुछ आफिसिज को उपयोग कर के पाकिस्तान की इन हरकतों को बन्द करने की कोशिश की, लेकिन इस में उस को भी असफलता मिली, क्या इस आशय का कोई संदेश रूस से मिला है ?

श्री दिनेश सिंह : इस सवाल पर इस सदन में कई मर्तबा विस्तारपूर्वक बात हो चुकी है। मैंने पिछली बार भी प्रश्न किया था—और अभी

वह स्थिति नहीं बदली है—कि ताशकंद घोषणा के अनुसार जो काम हम मुनासिब समझते थे, वह हमने किया है। पाकिस्तान को जो काम करना चाहिए था, वह उस ने नहीं किया। इस बात की सूचना रूस और अन्य मित्र देशों को दी गई है। यहां भी इस की जितनी चर्चा हुई है, उसकी खबर भी चारों तरफ है। दिक्कत यह है कि सब लोगों की एक राय होते हुए भी, ताशकंद घोषणा में शामिल होते हुए भी, पाकिस्तान की स्थिति को नार्मलाइज करने के लिए जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह उस ने अभी तक नहीं की है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी: मेरा सवाल यह है कि क्या इस सम्बन्ध में रूस ने अपने गुड आफिसिज का उपयोग किया है और क्या रूस को उस में असफलता हुई है।

श्री विनेश सिंह: सफलता नहीं मिली है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रूस ने भी जरूर कोशिश की होगी।

एक भावनात्मक सवाल: की होगी या की है ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी: यदि रूस को भी इस मामले में असफलता हुई है, तो क्या सरकार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जायेगी ?

श्री विनेश सिंह: जी नहीं।

श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या मंत्री महोदय का ध्यान अयूब साहब के हाल के वक्तव्य की ओर गया है; यदि हां, तो क्या उस से उन को ऐसी आशा लगती है कि इस दिशा में कुछ प्रगति होगी? हमारा जो माल रोका गया है, उस का मूल्य कितना है? अगर पाकिस्तान उस माल को वापस देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में आगे और क्या कठोर कदम उठाया जायेगा ?

1802 (A1) LSD—2.

श्री विनेश सिंह: मैं ने पिछली मर्तबा ये सब आंकड़े सदन को दिये थे। मैं फिर अर्ज कर दूँ कि पाकिस्तान ने हमारा जो कारगो जप्त किया था, उस की लागत लगभग 9,31, 19, 017 रुपये है, जिस में से उस ने 70' 14 लाख रुपये का माल वापस कर दिया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय: मैं ने यह भी पूछा है कि क्या अयूब साहब के हाल के वक्तव्य से मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में प्रगति की कोई आशा नजर आती है।

श्री विनेश सिंह: इस के बारे में मैं क्या अर्ज करूँ? आशा तो हमेशा ही रखनी चाहिए।

Shrimati Jyotsna Chanda: Do Government propose to pay compensation to the traders whose goods were seized by Pakistan during the Indo-Pakistan conflict? If so, when? If not, will the Government consider it?

Shri Dinesh Singh: Most of these goods were insured and the insurance companies are trying to get them released. Failing that, for those which have been insured by the insurance companies, the neutral powers so to say will pay the insurance value.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: श्रीमान्, पाकिस्तान का कुछ माल हम ने रोक लिया था। क्या वह सारा माल हम लौटा चुके हैं? यदि हां, तो क्या हम यह रेसिप्रोकल नीति नहीं बरत सकते थे कि जिस अनुपात में पाकिस्तान लौटावे उतना ही हम लौटाते रहें? यह नीति बरती गई या नहीं?

श्री विनेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप को स्मरण होगा, पिछले मर्तबे मैं ने इस का विस्तारपूर्वक जवाब दिया था, काफी इस का डिस्कशन हुआ था। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम ने जो पाकिस्तान का सामान यहां रोका था वह 27. 15 करोड़ का था, वह तो पूरी एनीमी प्रापर्टी का था और उस में कारगो जितना था वह केवल 1. 5 करोड़ का था और

मने यह फैसला किया था कि यह हम उन को वापस कर देंगे।

Shri Vikram Chand Mahajan: May I ask the hon. Minister what was the hurry which forced the Government of India to return the Pakistani cargo earlier than their beginning to return the Indian cargo?

Shri Dinesh Singh: Our desire to normalise relations in view of the Tashkent declaration.

Shri P. Venkatasubbaiah: The hon. Minister just now said that the insurance companies which have insured these goods will be taking adequate steps to pay the value that has been involved in this cargo that has been impounded during the Indo-Pak conflict. May I know, since these are extraordinary circumstances, whether the Government proposes to expedite the matter and if necessary give necessary assistance to the insurance companies or the individuals concerned so that they may not suffer for no fault of theirs?

Shri Dinesh Singh: Yes, Sir. Whatever we can do, we shall certainly help.

Shri Hem Barua: In pursuance of the Tashkent Pact a conference of the Indian and Pakistani Commerce Ministers was held at Rawalpindi where a decision was taken to release the goods captured by both the countries. Pakistan failed to do it. Now that the Pakistani President has said that he wants to normalise relations with India, a statement which our Prime Minister has welcomed, may I know whether our Government have told President Ayub Khan that as evidence of his good intention he should release the cargoes immediately?

Shri Dinesh Singh: We have been constantly reminding the Pakistan Government to have a meeting on this subject, so that we can discuss the release of cargoes.

Shri Hem Barua: I am not interested in a meeting. There was a meeting

already at Rawalpindi, and the meeting came to a decision for the release of these goods. I am not interested in any more meetings. I am interested in knowing whether our Government have told President Ayub Khan point blank that as an evidence of his intention to normalise relations with India, he should start with releasing the cargoes that are in the custody of Pakistan.

Shri Dinesh Singh: It is more a suggestion for action. We have not yet conveyed to him anything on this point.

Shri Hem Barua: If the Government has not done so far, then what was the purpose in the Prime Minister issuing a statement welcoming President Ayub Khan's statement!

Mr. Speaker: That is an entirely different question.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Since our undue haste to normalise relations with Pakistan has landed us into the most abnormal situation of being at the loser's end, does the Minister, in collaboration with the hon. Shipping Minister, propose to take up this issue with the international shipping lines to advise them not to call on the Pakistani ports unless these cargoes are returned?

Shri Dinesh Singh: This is a much more complicated issue. All these suggestions that the hon. members have made we will certainly consider.

Shri S. Kundu: What are the types of goods that the Pakistan Government has impounded, and secondly what is the reply, if any, from the Pakistan Government to the letter of the Commerce Minister seeking the release of the impounded goods?

Shri Dinesh Singh: They have said nothing. We have been pressing that "let us meet to discuss this thing along with the other things." Also, our High Commissioner has mentioned on several occasions that we would like this

to be released. They have not said anything so far. Regarding the nature of the cargo, it is of various kinds, machinery and other goods also.

श्री कंबर लाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कारगो के अतिरिक्त वहां पर पाकिस्तान में बहुत से कारखाने भी रह गए हैं और खास तौर से दिल्ली के कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिन के कारखाने रह गए हैं, तो क्या उन कारखानेदारों ने आपके पास कोई रेप्रेजेंटेशन भेजा है कि हमारे पाकिस्तान में इतने कारखाने रह गए, बहुत नुकसान हुआ, हम सफरर्स हैं, हमें कुछ सहायता दीजिए? सहायता पैसे की नहीं, क्रेडिट फैसिलिटी, बिजली, जमीन आदि की। क्या सरकार उस रेप्रेजेंटेशन पर विचार कर रही है? यदि कर रही है तो क्या कार्यवाही अब तक की है?

श्री विनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो हमारी अचल सम्पत्ति हिन्दुस्तान की पाकिस्तान सरकार ने ली है वह लगभग सवा दस करोड़ की है। जहां तक कि उस को यहां मजदूरी देने की बात है मैं एकदम से नहीं कह सकता कि हमारा जो पुनर्वास मंत्रालय है उस ने उन के लिए क्या किया?

Introduction of Second Class Sleeper Coaches

+

- *1593. **Shri Sradhakar Supakar:**
Shri Hukam Chand Kachwal:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Y. S. Kushwah:
Shri G. C. Dixit:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is proposed to introduce Second Class sleeper coaches in all long distance trains in India;

(b) if so, the amount of expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) the routes to be covered and the time by which these coaches are likely to be introduced?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Parimal Ghosh):
 (a) No, Sir.

(b) For providing Second Class Sleeper Coaches on selected long distance B.G. trains, the rolling stock programme for the Fourth Five Year Plan has a firm provision of 50 and a tentative provision for 60 B.G. Second Class Sleeper coaches. The total cost of these 110 coaches is estimated to be Rupees two crores and twenty two lakhs approximately. The present proposal is to introduce Second Class Sleeper Coaches on Kalka-Delhi-Howrah, Delhi-Madras, Amritsar-Delhi-Bombay, Bombay-Howrah and Bombay-Madras routes. These services are likely to commence being introduced on these routes from October, 1967.

Shri Sradhakar Supakar: May I know, having regard to the limits of the hauling capacity of these long-distance trains, whether the provision of second class sleeper coaches will be to the detriment of the third class sleeper coaches?

Shri Parimal Ghosh: No, Sir. The second class sleeper coaches will not interfere in anyway with the third class sleeper coaches.

Shri Sradhakar Supakar: May I know whether the provision of the second class as a whole is not to the disadvantage of the passenger traffic, in the sense that the second class passengers and those travelling in coaches other than sleeper coaches pay a higher amount but do not enjoy the same amenity as enjoyed by the third class passengers in sleeper coaches?

Shri Parimal Ghosh: The present system in the second class coaches is, half of these coaches is being given for sleeper berths and the other half is for sitting accommodation. This actually is causing some inconvenience for those who are having sleeper berths. So, in view of this, we have now evolved a new system of coaches in which the sleeper berths will be exclusively given to those who want to travel in sleeper coaches. There